खाद्य प्रसंस्करण की 250 करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी जल्द

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 250 करोड़ रुपये के निवेश वाली 12 परियोजनाओं की स्थापना के लिए जल्द स्वीकृति मिल सकती है। इन परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद अप्रेजल समिति ने इन्हें स्वीकृति दे दी है। अब इन प्रस्तावों को राज्य स्तरीय एंपावर्ड समिति (एसएलईसी) के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

नीति के तहत आने वाले प्रस्तावों के परीक्षण के लिए गठित अप्रेजल समिति की शनिवार को अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीना की अध्यक्षता में आइआइए सभागार में बैठक हुई। बैठक में 17 प्रस्तावों का

- अप्रेजल समिति ने राज्य स्तरीय एंपावर्ड समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए दी स्वीकृति
- अब तक 10 हजार करोड़ की 416 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं

प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति ने 12 प्रस्तावों को नीति के तहत अर्ह पाया। इनमें व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आइक्यूएफ) के चार, बेकरी के दो और लालीपाप कैंडी, फिश फीड, ग्राउंड नट बायल, आइसक्रीम, रेडी टू ईट और टोमैटो केचप के एक-एक प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने एचवीआर फूड्स, जौनपुर के निवेशक हर्षवर्धन सिंह को मसाला उत्पादन की आधुनिक इकाई को पूर्ण व्यवस्थित करने व उत्पादन प्रारंभ करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। बैठक में बताया गया कि नीति के तहत अब तक 10 हजार करोड़ रुपये की 416 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 70 परियोजनाएं क्रियाशील होकर उत्पादन कर रही हैं और अगले छह माह में 100 और परियोजनाओं के क्रियाशील होने की संभावना है। निवेशक सौर ऊर्जा से संयत्रों के संचालन को प्राथमिकता दे रहे है। अब तक 58 परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है।

अब उप्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक कहलाएगा यूपीसीबी

राब्यू, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) का नाम अब 'उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि.' होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस बदलाव से बैंक को राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। बैंक के प्रबंध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ के मुताबिक बैंक के नाम में स्टेट शब्द जुड़ने से बैंक की राज्य स्तरीय पहचान बनेगी। ग्राहकों के बीच बैंक की साख भी बढ़ेगी।